अपने स्वार्थ की वजह से या अपनी दोस्ती की वजह से किसी एक व्यक्ति की या तो फेवर में बोल रहा है या खिलाफ बोल रहा है। तो यह आपकी इमेज को बचाने के लिए भी है, सिर्फ उस पोस्ट को रेफर कर दें, नाम न लें।

श्री शिवचरण सिंह: मेरा उद्देश्य तो केवल विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए है, मुझे दूसरी बातों से कोई लेना-देना नहीं है। यह मिनिस्टर जो बाकी बचे हैं यह भी हवाला में चले जाएं तो भी मुझे कुछ लेना-देना नहीं। मुझे तो केवल प्रशासनिक दृष्टि से जो विद्यार्थियों का अहित हो रहा है, उस बारे में कहना था। यह तो हवाला जाना ही जाना है, यह महकमा तो ले ही जाएगा।

उपसभापति: मंत्रियों का आप नाम ले लीजिए क्योंकि मंत्री तो यहां रहते हैं।

श्री शिवचरण सिंह: मंत्री तो गए अर्जुन सिंह गए, सिंधिया गए। बहन शैलजा हैं बची हुई तो उनके लिए मैं नहीं चाहता कि वे जाएं।

उपसभापति: महिलाओं के साथ आपको इतनी सहानुभूति है, इसके लिए हम आप के शुक्रगुजार हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदया, मेरा कहना यह है कि कम से कम जो कामेश्वर झूठा सर्टिफिकेट देकर छुट्टी लेकर चली गई, उसके खिलाफ तो कार्रवाई करें।

श्री इकबाल सिंह (पंजाब): मैडम, यह आडवाणी जी का नाम नहीं लेना चाहते हवाला में।

THE DEPUTY CHAIRMAN: We do not take names. Let us be more positive in our attitude, बच्चों के मामले में।

Need to formulate a Comprehensive scheme and take effective steps for Overall Development of Afforestation for Maintaining Agricultural Production in the state of Punjab

श्री इकबाल सिंह (पंजाब): मैडम, मैं आपके माध्यम से इस विशेष उल्लेख के द्वारा सरकार का पंजाब राज्य में वनों का क्षेत्रफल बढ़ाने की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैडम, वृक्ष पृथ्वी की शोभा है, पृथ्वी को हरी-भरी बनाने के लिए भूमिगत के नियंत्रण के लिए जमीन में पानी की ऊंची सतह बरकरार रखने के लिए उद्योगों की वृद्धि के लिए, कृषि पैदावार को बढ़ाने के लिए राष्ट्र को अकाल से बचाने के लिए, फल, लकड़ी, जड़ी-बूटी आदि की प्राप्ति के लिए देश में जंगलों का विकास करना बहुत आवश्यक है।

मैडम, पंजाब राज्य में वनों का क्षेत्रफल जरूरत से बहुत कम है। पंजाब में देश के कुल वनों में से 7 प्रतिशत इलाके में वन हैं, जबकि राज्य में कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए, ट्यूबवैलों के लिए जमीन में पानी की ऊंची सतह बरकरार रखने के लिए और पंजाब में मौजूदा कृषि पैदावार कायम रखने के लिए 25 प्रतिशत वन तथा वृक्षों का होना बहुत आवश्यक है। अगर पंजाब राज्य में वनों के क्षेत्रफल तथा वृक्षों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई तो आने वाले दस सालों के बाद ट्यूबवैलों के पानी की सतह बहुत नीचे चली जाएगी और इसका पंजाब राज्य की कृषि पैदावार पर बहुत घातक प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर राज्य में वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि करने से खेती की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, खेती फले-फूलेगी, जमीन में पानी की कमी नहीं होगी और यह मानवमात्र के लिए कल्याणकारी होंगे। पेट्रोलियम पदार्थों के प्रयोग से, फ्यूल के जलने से, मिल-फैक्टरियों के कचरे और चिमनी के धुएं से निकलने वाली गंदी हवा के बदले में वृक्ष शुद्ध हवा छोड़ते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षों को लगाना मानव का कल्याण करना है।

इसलिए, मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि पंजाब राज्य में वनों का क्षेत्रफल, जो वर्तमान समय में केवल 7 प्रतिशत ही है, उसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक करने संबंधी एक योजना का निर्माण किया जाए और राज्य में जंगलों का विकास करने तथा वृक्षों की संख्या में वृद्धि करने संबंधी ठोस व प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि राज्य की कृषि पैदावार पर विपरीत प्रभाव न पड़े। राज्य के किसानों के हित में वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि करना बहुत आवश्यक है। कृषि की उन्नति से ही उद्योगों की उन्नति संभव है, अत: इस संबंध में सरकार आश्यक कदम उठाए। धन्यवाद।

उपसभापति: अभी लंच का समय हो गया है लेकिन अभी चार नाम और हैं। यदि आप कहें तो बाकी के स्पेशल मेंशन 2.00 बजे करेंगे।

कई माननीय सदस्य: 2.00 बजे करेंगे।

उपसभापति: चार-पांच नाम अभी हैं। यह जो चार-पांच नाम अभी हैं, 2.00 बजे पहले इनको कर लेंगे और उसके बाद After that, we will have discussion on U.P. till 4 o'clock. At 4 o'clock, there will be the Prime Minister's reply on the Motion of Thanks on the President's Address.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): 2 घंटे का टाईम मत कट कीजिएगा इसके कारण।

उपसभापति: ठीक है, अगर आप लोग लड़ाई-झगड़ा नहीं करेंगे.....**(व्यवधान)** मैं तो बिल्कुल लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहती .....**(व्यवधान)**

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया): अपनी आंखों पर जोर मत डालो, आपरेशन है, टांके कट जाएंगे, दो-चार दिन घर में बैठकर आराम करो।

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): प्राईम-मिनिस्टर के जवाब के बाद ले लीजिए।

श्री एस०एस० अहलुवालिया: मैडम, 2 बजे ले लीजिए।

उपसभापति: ठीक है, 2 बजे ले लेंगे। दो-तीन हैं, जल्दी-जल्दी बोल लेंगे, पांच-पांच मिनट।

The House is adjourned till 2 o'clock for lunch.

The House then ajourned for lunch at six minutes past one of the clock

---

The House reassembled after lunch at six minutes pass two of the clock, (SHRI SATISH AGARWAL) THE VICE-CHAIRMAN, in the Chair.

SPECIAL MENTIONS —CONTD.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Now we shall take up the Special Mentions first.

Serious Crisis in I.D.P.L. due to Inconsistent Government Policy and Lack of Funds

SHRI N. GIRI PRASAD (Andhra Pradesh): Sir, this is about IDPL which has got five units in different States. It is now facing a serious crisis. I am sorry to mention that I raised this issue earlier also. Many other Members also raised this issue. But, unfortunately, due to a callous attitude on the part of the Government, no improvement took place. Besides that, now it is facing a serious crisis. The point is that it is a forerunner pharmaceutical industry in the whole of the country. It could prepare quality drugs at affordable prices to the people. It could be dovetailed into our national health plan. In spite of all these potentialities, the Government has not taken care to do something for it in a positive direction. Now, the Government has found the BIFR route to kill this public sector unit and they do not provide funds. Then in that case a viable unit falls sick and they would pronounce it dead because it falls sick. So, against this background I will try to briefly state a bit of chronology here. Sir, the IDPL was referred to the BIFR in May 1992. The BIFR approved a revival plan on 10.2.94. But the targets could not be achieved mainly because the Government failed to provide working capital besides local imposition of power cuts, etc. The BIFR directed the IDPL management to work out a modified revival plan on 28.5.95. So, accordingly the management prepared a revival plan in June 1995 and it was submitted to the Government. The interesting thing is that the Government slept over this plan for eight months without doing anything, without providing funds and without taking any positive steps. All of a sudden on 17th January, 1996, the Government addressed a letter to the BIFR saying that it could not commit funds without verifying its viability. For that, in order to find out the